

PSC द्वारा MGNREGA योजना में सुधार का सुझाव

प्रलिस के लिये:

[ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति](#), [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना](#), [आधार-आधारति भुगतान प्रणाली](#), [आधार](#), [ग्राम पंचायत](#), [लोकपाल](#), [मुद्रास्फीति](#), [राष्ट्रीय मोबाइल नगरानी प्रणाली](#), [कृषि श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक](#), [राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी](#), [उपभोक्ता मूल्य सूचकांक \(CPI\)](#) ग्रामीण, [लोकसभा अध्यक्ष](#) ।

मेन्स के लिये:

मनरेगा योजना से संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह ।

[स्रोत: लाइवमटि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति \(PSC\)](#) ने उन चुनौतियों पर प्रकाश डाला है जिससे [MGNREGS](#) के तहत [मजदूरी](#), [मुद्रास्फीति](#) के अनुरूप नहीं हो पाई है और इसने [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना \(MGNREGS\)](#) में कुछ सुधारों की सफारिश की है ।

नोट: मुद्रास्फीति से तात्पर्य धन की क्रय शक्ति में कमी से है जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि के माध्यम से स्पष्ट होती है ।

मनरेगा के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **मजदूरी दर का मुद्रास्फीति के अनुरूप न होना:** मनरेगा मजदूरी दर मुद्रास्फीति के अनुरूप न होने से ग्रामीण श्रमिकों की क्रय शक्ति में कमी आती है और ये **100 कार्यदिवस पूरा करने से हतोत्साहित** होते हैं ।
 - इसके अतिरिक्त **100 दिन की रोजगार गारंटी प्रायः अपर्याप्त** (वर्षा रूप से प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के बाद की स्थिति में) सिद्ध होने से ग्रामीण परिवारों को **दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा** प्रदान करने की इसकी क्षमता सीमित हो जाती है ।
- **अनुमेय कार्यों में संशोधन:** मनरेगा कार्य सूची प्रायः बाढ़ सुरक्षा और भूमि अपरदन प्रबंधन जैसी ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करने में **वफिल** रहती है ।
 - स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अनुमेय कार्यों को संशोधित करने में विलंब, क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में योजना की प्रभावशीलता को सीमित करता है ।
- **मजदूरी का विलंबित भुगतान:** भुगतान में देरी अक्सर **आधार-आधारति भुगतान प्रणाली (ABPS)**, **नषिक्रयि आधार** वविरण, या **फ्रीज हुए बैंक खातों** के कारण होती है, जिससे योजना का अपेक्षित प्रभाव प्रभावित होता है ।
 - संभावित **तकनीकी खामियों** और बुनियादी ढाँचा संबंधी समस्याओं के कारण कमजोर श्रमिकों को भुगतान नहीं मिला पाता ।
- **मुआवजे में विलंब:** मजदूरी के भुगतान में विलंब के मामले में, लाभार्थी विलंब अवधि के लिये **प्रतिदिन अवैतनिक श्रम के 0.05%** की दर से **मुआवजे** के हकदार हैं ।
 - हालाँकि देश में अधिकांश स्थानों पर विलंब मुआवजे के भुगतान का **पालन नहीं किया जाता है** ।
- **बेरोजगारी भत्ता:** मनरेगा के अंतर्गत जो व्यक्त काम के लिये आवेदन करते हैं, लेकिन उन्हें 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, वे **दैनिक बेरोजगारी भत्ते** के हकदार होते हैं ।
 - बेरोजगारी भत्ता **शायद ही कभी दिया जाता है** और दी जाने वाली राशि भी **न्यूनतम होती है** ।
- **कमजोर सामाजिक अंकेक्षण:** मनरेगा के अंतर्गत, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के अंतर्गत शुरू की गई सभी परियोजनाओं का **नियमित सामाजिक अंकेक्षण करना चाहिये** ।

- हालाँकि वर्ष 2020-21 में केवल 29,611 ग्राम पंचायतों का कम-से-कम एक बार ऑडिट किया गया, जो कमज़ोर सामाजिक ऑडिट तंत्र को दर्शाता है।
- लोकपालों की कमी: 715 संभावित नयिकृतियों में से अभी तक केवल 263 लोकपालों की नयिकृती की गई है।

समिति द्वारा मनरेगा में सुधार हेतु सुझाव की वभिन्न सफ़ारशें क्या हैं?

- **मजदूरी दरों में संशोधन:** पारशिरमकि दरों में ग्रामीण क़षेत्रों में **जीवन नरिवाह की बढ़ती लागत** के दृष्टिगत मौजूदा मुद्रासफ़ीती के अनुरूप **उपयुक्त मुद्रासफ़ीती सूचकांक** के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिये।
 - **आधार वर्ष 2009-2010** और दरों को **वर्तमान मुद्रासफ़ीती उपनति** और **ग्रामीण आर्थिक स्थितियों** के अनुरूप अद्यतन करने की आवश्यकता है।
- **कार्य दविसों में वृद्धि:** समतिने मनरेगा के अंतर्गत कार्य दविसों की संख्या को **100 से बढ़ाकर 150 करने की भी सफ़ारशि की।**
- **भुगतान तंत्र:** इसने नरिबाध वेतन संवतिरण सुनश्चिति करने के लिये APBS के साथ-साथ **वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों** को बनाए रखने की सफ़ारशि की।
 - पैनल ने समय पर वेतन भुगतान सुनश्चिति करने के लिये एक **सुव्यवस्थति भुगतान प्रक्रिया** की सफ़ारशि की, जिसका उद्देश्य नौकरशाही बाधाओं को कम करना है।
- **राष्ट्रीय मोबाइल नगिरानी प्रणाली (NMMS):** समतिने लाभार्थियों को **NMMS** का प्रभावी उपयोग करने में सहायता के लिये **जागरूकता अभियान और प्रशक़िषण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया।**
 - इसने तकनीकी समस्याओं के कारण श्रमकों द्वारा योजना से बाहर होने से बचाने के लिये **वैकल्पिक उपस्थतिपद्धति** को बनाए रखने की भी सफ़ारशि की।
 - NMMS की सहायता से पारदर्शति और जवाबदेही बढ़ाने के लिये मनरेगा के अंतर्गत **उपस्थति और कार्य प्रगति** की नगिरानी की जाती है।
- **मनरेगा के लिये पर्याप्त नधि आवंटन:** समतिने सरकार द्वारा मनरेगा के लिये पर्याप्त वतितीय आवंटन सुनश्चिति करने की आवश्यकता पर **बल दिया** ताक गिरामीण परिवारों को आजीविका सुरक़षा प्रदान करने में इसकी प्रभावशीलता सुनश्चिति हो सके।

नोट:

- वतितीय वर्ष **2024-25** में संपूर्ण भारत में औसत मनरेगा पारशिरमकि में **प्रतदिनि केवल 28 रुपए की वृद्धि हुई।**
 - **वतितीय वर्ष 2023-24** में मनरेगा पारशिरमकि वृद्धि **2% से 10%** तक रही।
- भारत सरकार **कृषि श्रम के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL)** का उपयोग करके मनरेगा के तहत पारशिरमकि दर अधिसूचिति करती है।
- **राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (NMW)** के नरिधारण की कार्यप्रणाली की समीक़षा और सफ़ारशि करने के लिये गठतिडॉ. **अनूप सत्पथी समति (2019)** ने सफ़ारशि की थी कि मनरेगा के तहत मजदूरी **375 रुपए प्रतदिनि होनी चाहिये।**
- **डॉ. नागेश सहि समति (2017)** ने मनरेगा मजदूरी को **CPI-कृषि श्रम के बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) गिरामीण** के अनुसार अनुक्रमति करने की सफ़ारशि की।

ग्रामीण वक़िस एवं पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समति क्या है?

- **परचिय:** इसे पहली बार **5 अगस्त, 2004** को **लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नयिमों के 331C** के अंतर्गत ग्रामीण वक़िस से संबंधति मुद्दों पर ध्यान केंद्रति करने के लिये गठति किया गया था।
- **अधिकारति:** नमिनलखिति **मंत्रालय/वभिग** पर समतिकी अधिकारति है:
 - **ग्रामीण वक़िस मंत्रालय**
 - **पंचायती राज मंत्रालय**
- **संरचना:** समतिमें अध्यक्ष द्वारा **लोकसभा से नामति 21 सदस्य** और सभापति द्वारा **राज्यसभा से नामति 10 सदस्य, कुल 31 सदस्य** शामिल हैं।
 - कसिी मंत्री को समतिके सदस्य के रूप में **नामति नहीं कयिा जाता है।**
 - समतिके अध्यक्ष की नयिकृती **लोकसभा अध्यक्ष** द्वारा **समतिके सदस्यों में से** की जाती है।
- **सदस्यों का कार्यकाल:** समतिके सदस्यों का कार्यकाल **एक वर्ष से अनधिक होता है।**
- **कार्य:**
 - **अनुदानों की मांगों पर** वचिार करना और सदनों को सूचना देना।
 - अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रेषति **वधियकों की जांच करना तथा उनकी सूचना देना।**
 - मंत्रालयों/वभिगों की **वार्षिक रिपोर्ट की समीक़षा करना और उनकी सूचना देना।**
 - अध्यक्ष या सभापति द्वारा संदर्भति **राष्ट्रीय नीतिदस्तावेज़ों पर वचिार करना और सूचना देना।**

MGNREGS

- **परचिय:** ग्रामीण वक़िस मंत्रालय द्वारा वर्ष **2005** में शुरू कयिा गया, MGNREGS सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है, जिसके

अंतरगत प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को न्यूनतम वेतन पर 100 दिनों का शारीरिक कार्य प्रदान किया जाता है।

■ कार्यान्वयन: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ मलिकर योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

■ प्रमुख विशेषताएँ:

- वधिक गारंटी: मनरेगा की मुख्य विशेषता इसके अंतरगत कार्य की वधिक गारंटी है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के वयस्कों द्वारा कार्य का अनुरोध किये जाने पर 15 दिनों के भीतर कार्य प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाता है।
- बेरोज़गारी भत्ता: यदि 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोज़गारी भत्ता प्रदान किया जाना होता है।
- महिला वर्ग का समावेशन: इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है तथा लाभुकों में न्यूनतम एक तहई महिलाओं का होना सुनिश्चित किया जाता है, जिन्होंने पंजीकरण कराया हो तथा काम के लिये अनुरोध किया हो।
- सामाजिक अंकेक्षण: महात्मा गांधी नरेगा, 2005 की धारा 17 में ग्रामसभा द्वारायोजना कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का अधिदेश वर्णित है।

■ लागत सहभागिता: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

■ संवदाकार पर प्रतबंध: संवदाकारों की नयिकता और श्रमिकों का वसिथापन करने वाली मशीनों के उपयोग पर प्रतबंध है।

नषिकर्ष

- मनरेगा के लिये संसदीय स्थायी समिति की सफारिशों का उद्देश्य अपर्याप्त कार्यदविस, पारश्रमिक असमानता, वलिंबति भुगतान और अनुपयुक्त नगिरानी प्रणाली जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। ग्रामीण आजीविका में सुधार और दीर्घावधि में योजना की स्थरिता सुनिश्चित करने के लिये इन सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

दृष्टाभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के कार्यान्वयन की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये और इसकी प्रभावकारिता बढ़ाने हेतु सुधारों का सुझाव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियिम" से लाभानवति होने के पात्र हैं? (2011)

- (a) केवल अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात परिवारों के वयस्क सदस्य
- (b) गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (c) सभी पछिड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (d) किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. भारत में आज भी सुशासन के लिये भूख और गरीबी सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं. मूल्यांकन कीजिये कि इन वशाल समस्याओं से नपिटने में सरकारों ने कतिनी प्रगति की है। सुधार के उपाय सुझाइये। (2017)

प्रश्न. क्या कमज़ोर और पछिड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नतिके लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहष्कृत कर देती हैं? (2014)